Policy of liberalisation in the Eighth Five Year Plan

416. PROF. C. LAKSHMANNA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that liberalisation would form a major thrust in the planning process for the Eighth Five Year Plan;

(b) if so, what would be its effect on the commanding heights enjoyed by public sector industries in the plans so far; and

(c) whether some of the core sector projects are likely to be made open for the private investments as a result of this change in the policy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI BIREN SINGH ENGTI): (a) to (c) The Strategy for the Eighth Five Year Plan has not yet been formulated.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

417. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं ; और

(ख) इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक भर दिए जाने की संभावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) तारीख 25-4-88 को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों और अपर न्यायाधीशों के 60 स्वीकृत पदों में से, नीचे उपदर्शित तारीखों से, 9 पद रिक्त थे :

अपर न्यायाधीश	स्थायी न्यायाधीश
15-10-84	19-11-87
15-10-84	06-01-88
15-10-84	30-01-88
15-10-84	11-04-88
15-10-84	

उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार, स्थायी रिक्त पदों को पहले भरना होता है, इसलिए अपर न्यायाधीशों के रिक्त पद नहीं भरे गए जबकि अक्तूबर, 1984 से स्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती रही है ।

(ख) न्यायाधीशों का चयन, संबंधित संवैधानिक प्राधिकारियों के साथ परामर्श और विचार-विमर्श करके, किया जाता है और यह एक निरन्तर चलने रहने वाली प्रक्रिया है । सरकार न्यायाधीशों के रिक्त पदों को शीघ्रता से भरे जाने के सभी संभव प्रयास करती है । इन रिक्त पदों को कब भरा जाएगा निश्चित रूप से यह बताना संभव नहीं है ।

उत्तर प्रदेश को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए योजना परिव्यय

418. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए वर्ष 1988-89 के वार्षिक योजना परिव्यय को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य